हिन्दी साप्ताहिक

हर्षिता टाइम्स

RNI Regn. No. UTTHIN/2008/28646

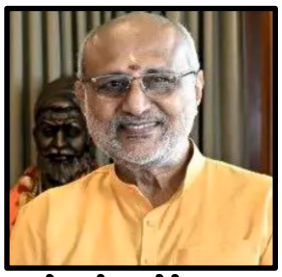

एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन देश के अगले उपराष्ट्रपति चुने गए हैं

ट्रंप टैरिफ पर वार्ता को तैयार मोदी बोले मैं भी मिलने को तैयार

• वर्ष : 17 • अंक : 35 • देहरादून • वृहस्पतिवार 11 सितंबर, 2025 • मूल्य : 1 रुपये • वार्षिक : 50 रुपये • पृष्ट : 4

जनता को त्वरित राहत और सुरक्षा देना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता- सीएम धामी

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में आयोजित समीक्षा बैठक में आपदा प्रबंधन, कानून व्यवस्था, पुनर्निर्माण कार्यों, पर्यटन एवं जनसुविधाओं से जुड़े महत्वपूर्ण निर्देश दिए। बैठक में शासन, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी और वर्चुअल माध्यम से सभी जिलाधिकारी शामिल हुए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता जनता को त्वरित राहत, सुरक्षा और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है। उन्होंने निर्देश दिए कि बरसात समाप्त होते ही पुनर्निर्माण और मरम्मत कार्यों में तेजी लाई जाए तथा आपदा प्रभावितों को मानकानुसार त्वरित सहायता दी जाए। उन्होंने कहा कि नदी-नालों के किनारे निर्माण पर रोक का सख्ती से पालन कराया जाए, उल्लंघन पर अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी। जिलाधिकारी अस्पतालों का नियमित निरीक्षण करें और डेंगू-मलेरिया जैसी बीमारियों की रोकथाम हेतु व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। कानून व्यवस्था पर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि संदिग्ध व्यक्तियों, अनधिकृत आधार कार्ड और वोटर आईडी जारी करने वालों पर कठोर कार्रवाई हो। सीमावतह्न क्षेत्रों में चेकिंग बढ़ाई जाए और गौवंश संरक्षण के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं।

चारधाम यात्रा के संदर्भ में मुख्यमंत्री ने कहा कि मानसून के बाद यात्रा को सतर्कता के साथ सुचारु कराया जाए और यात्रियों को मौसम संबंधी सूचनाएं समय पर उपलब्ध हों।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन 1905 और एंटी करप्शन नंबर 1064 की कार्यवाही निरंतर जारी रखी जाए। साथ ही डिजास्टर वॉलंटियर, संकट मोचन दल और मॉक ड्रिल के जरिए आपदा प्रबंधन को मजबूत किया जाए।

बैठक में प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव शैलेश बगोली, डीजीपी दीपम सेठ सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे, जबकि कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत वर्चुअल माध्यम से जुड़े।

हिमालय संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है सरकार : मुख्यमंत्री

देहरादून। हिमालय दिवस समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हिमालय केवल पर्वत श्रृंखलाओं का समूह नहीं है, बल्कि सम्पूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप का जीवन स्रोत है। उन्होंने कहा कि हिमालय की नदियां करोड़ों लोगों की प्यास बुझाती हैं और यहां पाई जाने वाली दुर्लभ जड़ी-बूटियां आयुर्वेद का आधार हैं। मुख्यमंत्री ने चेताया कि जलवायु परिवर्तन, अनियंत्रित विकास और प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन हिमालय के संतुलन को बिगाड़ रहे हैं। ग्लेशियरों के पिघलने से भविष्य में जल संकट और पारिस्थितिकीय असंतुलन की चुनौती गंभीर हो सकती है। उन्होंने कहा कि अप्रत्याशित क्लाउड बर्स्ट, भूस्खलन और तीव्र वर्षा जैसी आपदाएं लगातार बढ़ रही हैं।

उन्होंने बताया कि सरकार ने हिमालय संरक्षण के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित की है और नवंबर में राज्य में 'विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन' आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम, ग्लेशियर रिसर्च सेंटर, जल स्रोत संरक्षण अभियान और जनभागीदारी कार्यक्रमों के माध्यम से हिमालय की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में प्लास्टिक वेस्ट प्रबंधन के लिए 'डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम' शुरू किया गया है, जिससे हिमालयी क्षेत्र में 72 टन कार्बन उत्सर्जन कम करने में सफलता मिली है। उन्होंने कहा कि पर्यटन क्षेत्र में भी 'सस्टेनेबल टूरिज्म' को बढ़ावा देना जरूरी है ताकि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना पर्यटन का विकास हो सके।

उन्होंने यह भी कहा कि हिमालय संरक्षण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। पानी की बचत, पेड़ लगाना और प्लास्टिक का कम उपयोग जैसे छोटे-छोटे प्रयास भी हिमालय की रक्षा में अहम साबित हो सकते हैं। इसी क्रम में सरकार ने 2 से 9 सितंबर तक प्रतिवर्ष हिमालय जनजागरूकता सप्ताह मनाने का निर्णय लिया है।

इस अवसर पर पद्मभूषण डॉ. अनिल प्रकाश जोशी ने कहा कि अब साल दर साल आपदाओं का बढ़ना चिंता का विषय है और हमें हिमालय संरक्षण के लिए नए दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ना होगा। कार्यक्रम में विधायक किशोर उपाध्याय, मेयर सौरभ थपलियाल, दर्जाधारी मधु भट्ट, महानिदेशक यूकॉस्ट प्रो. दुर्गेश पंत, सूर्यकांत धस्माना सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

स्वास्थ्य विभाग में 300 चिकित्सकों की और होगी भर्तीः डॉ. धन सिंह रावत

देहरादून। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में 300 और चिकित्सकों की शीघ्र भतह्न की जायेगी। इसके लिये विभागीय अधिकारियों को राज्य चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड को अधियाचन भेजने के निर्देश दे दिये हैं। इसके अलावा विभाग में लम्बे समय से गैरहाजिर चल रहे 56 बॉण्डधारी डॉक्टरों की सेवाएं समाप्त कर दी गई है। सेवा से बर्खास्त इन चिकित्सकों से मेडिकल कॉलेज को अनुबंध के अनुरूप बाँड की धनराशी वसूलने के निर्देश भी दे दिये गये हैं।

सूबे के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने मीडिया को जारी बयान में बताया कि हाल ही में स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत प्रांतीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में चिकित्साधिकारी के 220 पदों पर डॉक्टरों की भर्ती की गई, जिनको प्रदेश के सुदूरवर्ती स्वास्थ्य केन्द्रों पर तैनाती भी दे दी गई है। इसके अलावा विभाग में चिकित्सकों के करीब 300 पद रिक्त पड़े हैं। इन पदों पर शीघ्र भर्ती के लिये विभागीय अधिकारियों को रोस्टर तैयार कर उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड को अधियाचन भेजने के निर्देश दे दिये गये

हैं, ताकि चयन बोर्ड समय पर भर्ती प्रक्रिया सम्पन्न कर विभाग को नये चिकित्सक उपलब्ध करा सके।

विभागीय मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में बेहतर हेल्थ सिस्टम तैयार करने में जुटी है, जिसके तहत सरकार सुदूरवर्ती क्षेत्रों की स्वास्थ्य इकाईयों में ढ़ांचागत व्यवस्थाओं से लेकर चिकित्सकों की तैनाती भी कर रही है, इसके अलावा सरकार ऐसे कार्मिकों को बाहर का रास्ता भी दिखने से गुरेज नहीं कर ही है जो अपनी जिम्मेदारियों के प्रति लापरवाह हैं। सरकार ने विगत माह राजकीय मेडिकल कॉलेजों से पासआउट 234 गैरहाजिर बॉण्डधारी चिकित्सकों के विरूद्ध वसूली के साथ ही बर्खास्तगी की कार्रवाई के निर्देश अधकारियों को दिये थे। जिसके फलस्वरूप गयाब चल रहे 178 चिकित्सकों ने वापस विभाग में ज्वाइनिंग दे दी है। जबकि 56 चिकित्सकों ने अंतिम चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। इन सभी गैरहाजिर 56 चिकित्सकों को बर्खास्त कर दिया गया है, साथ ही निदेशक चिकित्सा शिक्षा को गैरहाजिर सभी चिकित्सकों से बाण्ड की शर्तो के अनुरूप बाण्ड की धनराशि वसूलने के निर्देश भी दिये हैं।

डॉ. रावत ने बताया कि बताया कि प्रदेश के राजकीय मेडिकल कॉलेजों में एक अनुबंध के तहत छात्र-छात्राओं को न्यूनतम फीस में एमबीबीएस पढ़ाई कराई जाती है। इस अनुबंध के तहत इन छात्र-छात्राओं को एमबीबीएस की पढ़ाई सम्पन्न होने के बाद सूबे के पर्वतीय जनपदों के चिकित्सा इकाईयों में 5 वर्षो की सेवाएं देना अनिवार्य है। ऐसा न करने की स्थिति में इन चिकित्सकों को बाण्ड में निर्धारित धनराशि जमाकर विभाग से एनओसी लेनी होती है, तभी इन्हें इनके शैक्षिक प्रमाण पत्र लौटाये जाते हैं। अनुबंध की शर्तो का पालन न करने पर चिकित्सकों से बांड में निर्धारित धनराशि वसूलने का प्रावधान है।

प्रो. दिनेश चमोला 'शैलेश' को 'रघुनाथ कीर्ति हिंदी सेवा सम्मान 2025'

देहरादून। देश के प्रख्यात हिंदी साहित्यकार एवं साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार विजेता प्रो. (डॉ.) दिनेश चमोला 'शैलेश' को 'रघुनाथ कीर्ति हिंदी सेवा सम्मान 2025' से अलंकृत किए जाने की घोषणा हुई है। यह सम्मान केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, रघुनाथ कीर्ति परिसर, देवप्रयाग (उत्तराखंड) द्वारा प्रदान किया जाएगा।

विश्वविद्यालय के निदेशक प्रो. पी. वी. बी. सुब्रह्मण्यन ने जानकारी दी कि यह सम्मान प्रतिवर्ष उत्तराखंड मूल के किसी उत्कृष्ट हिंदी साहित्यकार को उनकी साहित्य सेवा के लिए दिया जाता है। इस वर्ष चयन समिति ने विभिन्न आवेदनों पर गहन विचार-विमर्श के बाद प्रो. चमोला को इसके लिए सर्वथा उपयुक्त पाया। सम्मान समारोह इसी माह देवप्रयाग में आयोजित होगा।

चार दशक से अधिक समय से साहित्य साधना में रत प्रो. चमोला ने हिंदी साहित्य की विविध विधाओं उपन्यास, कहानी, कविता, दोहा, लघुकथा, व्यंग्य, समीक्षा, अनुवाद, बाल साहित्य, एकांकी, शब्दकोश और स्तंभ लेखन में सात दर्जन से अधिक पुस्तकें लिखी हैं। उनके

साहित्य पर देश के अनेक विश्वविद्यालयों में एम.फिल. और पीएच.डी. स्तर के शोधकार्य संपन्न हो चुके हैं।

प्रो. चमोला को अब तक राष्ट्रीय स्तर पर 60 से अधिक सम्मान और पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें साहित्य अकादमी का बाल साहित्य पुरस्कार, 'साहित्यश्री', 'साहित्य शिरोमणि सम्मान', 'उत्तरांचल रत्न सम्मान', 'हिंदी गौरव सम्मान' और 'बाल साहित्यकार सम्मान' प्रमुख हैं।

हिंदी साहित्य के क्षेत्र में उनका योगदान नई पीढ़ी को प्रेरणा देता रहा है। उनकी कई पुस्तकें विद्यालयों और विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में शामिल की गई हैं। प्रो. चमोला ने संपादन के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय कार्य किया है और उनकी पत्रिका 'विकल्प' ने राष्ट्रीय स्तर पर विशेष पहचान बनाई है।

सम्पादकीय

धामी राज : उत्तराखंड में स्थिरता संघर्ष और सफलता की कहानी

उत्तराखंड का राजनीतिक इतिहास शुरू से ही अस्थिरता और लगातार बदलते नेतृत्व का साक्षी रहा है। सन् 2000 में जब यह राज्य उत्तर प्रदेश से अलग होकर अस्तित्व में आया, तब से लेकर अब तक शायद ही कोई मुख्यमंत्री ऐसा रहा जिसने अपना पूरा कार्यकाल आराम से पूरा किया हो। सत्ता परिवर्तन और राजनीतिक खींचतान इस प्रदेश की नियति बन गए थे। ऐसे परिदृश्य में मुख्यमंत्री 'पुष्कर सिंह धामी' का कार्यकाल एक अलग ही मिसाल पेश करता है। जुलाई 2021 में जब वे अचानक सत्ता के शीर्ष पर पहुंचे, तब न तो वे जनता के बीच बहुत परिचित चेहरा थे और न ही भाजपा संगठन में बड़े नेताओं की श्रेणी में गिने जाते थे। लेकिन आज, चार साल से अधिक का समय बीतने के बाद वे उत्तराखंड की राजनीति के सबसे केंद्रीय व्यक्तित्व बन चुके हैं।

धामी की जीवन यात्रा स्वयं संघर्ष और सादगी से जुड़ी है। पिथौरागढ़ जिले के टुंडी गांव में 1975 में जन्मे धामी अनुशासित सैनिक परिवार से आते हैं। यही कारण है कि उनके स्वभाव में परिश्रम, अनुशासन और सरलता झलकती है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से राजनीति की शुरुआत कर उन्होंने संगठनात्मक कार्यों का अनुभव प्राप्त किया और बाद में भाजपा युवा मोर्चा में सक्रियता दिखाई। 2012 में पहली बार खटीमा से विधायक चुने जाने के बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और धीरे-धीरे पार्टी में अपनी अलग पहचान बनाई।

जुलाई 2021 में जब भाजपा नेतृत्व ने तीरथ सिंह रावत की जगह उन्हें मुख्यमंत्री बनाया, तो यह निर्णय कई लोगों के लिए चौंकाने वाला था। लेकिन पार्टी को एक युवा और ऊर्जावान चेहरा चाहिए था, और धामी ने यह जिम्मेदारी आत्मविश्वास से संभाली। कोविड महामारी के बाद की आर्थिक चुनौतियाँ, बेरोजगारी का संकट, पर्यटन उद्योग की दुर्दशा और बार-बार आने वाली प्राकृतिक आपदाएँ इन सबके बीच उन्होंने जो नेतृत्व दिखाया, उसने उन्हें जनता के करीब ला दिया।

2022 का विधानसभा चुनाव धामी के लिए अग्निपरीक्षा थी। उन्होंने 'मिशन रिपीट' का नारा दिया और पूरे प्रदेश में जोश के साथ प्रचार अभियान चलाया। परिणामस्वरूप भाजपा ने 70 में से 47 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया। उत्तराखंड में यह पहला अवसर था जब सत्तारूढ़ पार्टी लगातार दूसरी बार सत्ता में लौटी। यद्यपि धामी स्वयं खटीमा से चुनाव हार गए, लेकिन पार्टी ने उन पर विश्वास बनाए रखा और उन्हें पुन: मुख्यमंत्री पद पर बनाए रखा। बाद में वे चंपावत उपचुनाव से विजयी होकर विधानसभा में लौटे। यह घटना उनकी छवि को और सुदृढ़ करती है कि 'हारकर भी जीतने वाले' नेता हैं।

धामी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि 'समान नागरिक संहिता' लागू करना है। लंबे विमर्श और विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के बाद जुलाई 2024 में इसे विधानसभा से पारित कराया गया और उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना जिसने इसे लागू किया। इसे धामी का राजनीतिक मास्टरस्ट्रोक माना गया। इसी तरह धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए सख्त कानून बनाना, धार्मिक पर्यटन के विकास पर ध्यान देना और महिला सशक्तिकरण के लिए विशेष योजनाएँ उनकी सरकार की प्रमुख पहलें रही हैं।

महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत आरक्षण और स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहन ने महिला मतदाताओं में धामी की लोकप्रियता बढ़ाई। युवाओं के लिए उन्होंने रोजगार योजनाएँ शुरू कीं, लेकिन भर्ती परीक्षाओं में हुए पेपर लीक कांड में धामी ने सख्त कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारियाँ कराईं और परीक्षा व्यवस्था में सुधार की पहल की।

बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी को लेकर भी धामी ने कई अहम कदम उठाए। ऑल वेदर रोड, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन, रोपवे और हवाई कनेक्टिविटी परियोजनाएँ तेज़ी से आगे बढ़ाई गईं। धार्मिक पर्यटन को नई ऊँचाइयों तक पहुँचाने के लिए बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण कार्य कराए गए। चारधाम यात्रा में रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं का आना इन प्रयासों की सफलता को प्रमाणित करता है।

फिर भी आपदाएँ धामी सरकार की सबसे बड़ी कसौटी साबित हुईं। जोशीमठ भू-धंसाव से लेकर 2025 में उत्तरकाशी के धराली क्षेत्र की आपदा तक, प्रशासन को जनता के गुस्से और पीड़ा का सामना करना पड़ा। राहत और मुआवजे के प्रयासों के बावजूद दीर्घकालिक रणनीति की कमी को लेकर आलोचना हुई। शहरी विकास, ट्रैफिक जाम और प्रदूषण जैसे मुद्दे भी जस के तस बने रहे।

राजनीतिक दृष्टि से धामी का सबसे बड़ा बल संगठन और केंद्रीय नेतृत्व का भरोसा है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह का समर्थन उन्हें न केवल स्थिरता देता है, बल्कि भविष्य की राजनीति में भी संभावनाएँ बढ़ाता है। उनकी विनम्र और सहज छवि जनता के बीच उन्हें लोकप्रिय बनाए रखती है।

आईएएस बंशीधर तिवारी : सेवा, समर्पण और संवेदनशील नेतृत्व की कहानी (2016 – 2025)

● पंकज कपूर

उत्तराखंड का प्रशासनिक ढांचा जितना जटिल है, उतना ही संवेदनशील भी। प्राकृतिक आपदाएँ, सीमित संसाधन, पलायन, शिक्षा और रोजगार की चुनौतियाँ यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों की असली परीक्षा लेती हैं। इन परिस्थितियों में यदि किसी अफसर ने अपने काम और कार्यशैली से खास पहचान बनाई है, तो उनमें एक नाम प्रमुखता से उभरता है। बंशीधर तिवारी (आईएएस 2016 बैच)। तिवारी जी का जीवन सफर इस बात का प्रमाण है कि अगर सेवा और समर्पण को ही लक्ष्य बनाया जाए, तो कितनी भी बड़ी जिम्मेदारी हो, उसे निभाना असंभव नहीं। पीसीएस से लेकर आईएएस बनने और फिर कई विभागों में अहम जिम्मेदारी संभालने तक उनका सफर बेहद प्रेरक है।

17 अक्टूबर 1978 को जन्मे बंशीधर तिवारी ने शिक्षा पूरी करने के बाद उत्तराखंड प्रशासनिक सेवा (पीसीएस) से अपने करियर की शुरुआत की। सेवा-भावना और कार्यनिष्ठा ने उन्हें तेजी से पहचान दिलाई। वर्ष 2016 में उन्हें आईएएस कैडर में प्रोन्नत किया गया। यहीं से उनके जीवन का एक नया अध्याय शुरू हुआ। आईएएस में शामिल होते ही उन्होंने कई अहम जिम्मेदारियाँ संभालीं और हर जगह अपनी कार्यशैली से जनता और सरकार का विश्वास जीता।

शिक्षा विभाग में उनकी पहचान एक सुधारक अधिकारी की बनी। जब उन्हें डीजी शिक्षा और राज्य परियोजना निदेशक (समग्र शिक्षा अभियान) का कार्यभार मिला, तब उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी-गुणवत्ता सुधार और सरकारी स्कूलों पर जनता का विश्वास लौटाना। उन्होंने स्मार्ट क्लासरूम और आईसीटी लैब्स के माध्यम से बच्चों को डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म से जोड़ने की पहल की। साथ ही शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यशालाएँ आयोजित कर शिक्षण पद्धति को आधुनिक बनाने पर ज़ोर दिया। पर्वतीय क्षेत्रों में पलायन रोकने के लिए शिक्षा की गुणवत्ता और आधारभूत ढाँचे पर ध्यान दिया गया। बेटियों की शिक्षा, छात्रवृत्ति और सुरक्षा के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए गए। इन पहलों से शिक्षा विभाग में नई ऊर्जा आई और तिवारी जी 'शिक्षा सुधारक' आईएएस के रूप में जाने जाने लगे।

इसके बाद उन्हें सूचना एवं जनसंपर्क विभाग का महानिदेशक बनाया गया। यहाँ उनकी सबसे बड़ी चुनौती थी-सरकारी योजनाओं को जनता तक पारदर्शी तरीके से पहुँचाना और प्रशासन व मीडिया के बीच सेतु का काम करना। उन्होंने डीआईपीआर को डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म से जोड़ा और सोशल मीडिया को सक्रिय कर जनता तक त्वरित सूचना पहुँचाना सुनिश्चित किया। आपदा के समय अफवाहों पर नियंत्रण और सही सूचना का प्रसार उनकी बड़ी उपलब्धि रही। उन्होंने मीडिया से सकारात्मक संवाद स्थापित कर सरकार और जनता के बीच विश्वास कायम किया।

शहरी विकास की चुनौतियों से निपटने के लिए उन्हें मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बनाया गया। इस जिम्मेदारी के दौरान उन्होंने स्मार्ट सिटी और शहरी योजनाओं पर काम किया। देहरादून की सबसे बड़ी समस्या-यातायात जाम को कम करने के लिए बहु-स्तरीय पार्किंग परियोजनाएँ शुरू कीं। रिस्पाना और बिंदाल जैसी नदियों के पुनर्जीवन के लिए विशेष योजनाएँ बनाई गईं। उन्होंने जनता से सीधे संवाद कायम कर शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत किया और पारदर्शी कार्यशैली पर ज़ोर दिया।

फरवरी 2025 में जब डीजी शिक्षा झरना कमठान प्रशिक्षण के लिए बाहर गईं, तो बंशीधर तिवारी को पुन: डीजी शिक्षा का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। यह कार्यकाल भले ही अल्पकालिक रहा, लेकिन उन्होंने तुरंत परीक्षा व्यवस्था की पारदर्शिता, शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया और डिजिटल संसाधनों की उपलब्धता से जुड़े फैसले लिए। यह उनके तेज़ और निर्णायक प्रशासनिक अंदाज को दर्शाता है।

जून 2025 में उनकी जिम्मेदारियाँ और बढ़ीं। उन्हें मुख्यमंत्री कार्यालय में एडिशनल सेक्रेट्री नियुक्त किया गया। इस दौरान उनके पास डीजी सूचना और उपाध्यक्ष एमडीडीए की जिम्मेदारियाँ भी रहीं। उन्होंने मुख्यमंत्री कार्यालय में रहते हुए विभिन्न विभागों के बीच तालमेल स्थापित करने और विकास कार्यों की मॉनिटरिंग पर काम किया। आपदा प्रबंधन में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। उत्तरकाशी-धराली जैसी आपदाओं के समय उन्होंने जनसम्पर्क और राहत कार्यों को तेज़ी से संचालित किया और जनता तक सही जानकारी पहुँचाई।

बंशीधर तिवारी की कार्यशैली का सबसे बड़ा आधार है-सेवा और समर्पण। वे मानते हैं कि प्रशासन केवल आदेश और नियंत्रण का तंत्र नहीं, बल्कि यह जनसेवा का माध्यम है। आलोचना और चुनौतियों के बावजूद उन्होंने ईमानदारी और संवेदनशीलता से कार्य किया। मीडिया रिपोर्टों में उनके बारे में यह उल्लेख मिलता है कि वे उन अधिकारियों में हैं जो अपने लिए नहीं, बल्कि जनता के लिए काम करते हैं।

उनके करियर में चुनौतियाँ भी कम नहीं रहीं। उत्तराखंड की बार-बार आने वाली प्रा तिक आपदाओं में उन्हें कई बार सूचना प्रबंधन और राहत कार्यों का नेतृत्व करना पड़ा। शिक्षा विभाग में सरकारी स्कूलों की गिरती साख को सुधारना सबसे कठिन चुनौती थी। वहीं एमडीडीए में अवैध निर्माण और भूमि विवाद जैसी समस्याओं के बीच विकास योजनाओं को आगे बढ़ाना उनके लिए संघर्षपूर्ण रहा।

इसके बावजूद उन्होंने कई उपलब्धियाँ हासिल कीं। शिक्षा सुधार और डिजिटल एजुकेशन का विस्तार, सूचना विभाग को तकनीकी रूप से आधुनिक बनाना, देहरादून-मसूरी क्षेत्र में शहरी नियोजन और पर्यावरण संरक्षण, तथा मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रशासनिक तालमेल और पारदर्शिता बढ़ाना उनकी बड़ी उपलब्धियाँ रही हैं।

2016 से लेकर 2025 तक उनकी यात्रा संघर्ष, सफलता और सेवा के अद्भुत मेल का उदाहरण है। वे उन अधिकारियों में गिने जाते हैं जो जनता की उम्मीदों पर खरे उतरते हैं। भविष्य में उनसे और भी बड़े कार्यों की उम्मीद की जा रही है। बंशीधर तिवारी न केवल एक सफल आईएएस अधिकारी हैं, बल्कि उत्तराखंड के युवाओं और भावी अफसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी हैं।

गढ़वाल विवि में बिना सीयूईटी के भी मिलेगा प्रवेश, शुरू हुई आवेदन प्रक्रिया

संवाददाता।

श्रीनगर। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए छात्रों को बड़ी राहत दी है। अब विश्वविद्यालय के परिसरों और संबद्ध महाविद्यालयों में बिना सीयूईटी स्कोर के भी दाखिला मिल सकेगा। विवि प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि ऐसे छात्रों को 12वीं कक्षा के अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर प्रवेश दिया जाएगा।

विश्वविद्यालय की ओर से आवेदन प्रक्रिया 7 सितंबर से शुरू हो चुकी है और 11 सितंबर इसकी अंतिम तिथि तय की गई है। इच्छुक छात्र-छात्राएं समर्थ पोर्टल के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्रो. ओपी गुसाईं ने बताया कि सामान्य श्रेणी के छात्रों को निर्धारित शुल्क देना होगा, एससी, एसटी और दिव्यांगजन वर्ग के लिए क्रमश: 400 और 200 रुपये का पंजीकरण शुल्क रखा गया है।

बीए एलएलबी, एलएलबी, एलएलएम, बीएड, एमएड, बीपीएड और एमपीएड को छोड़कर स्नातक एवं स्नातकोत्तर के सभी अन्य कार्यक्रमों की रिक्त सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा।

गढ़वाल विश्वविद्यालय से संबद्ध दून के प्रमुख महाविद्यालय में भी छात्र-छात्राएं इस प्रक्रिया के जरिए दाखिला ले सकते हैं।

विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि यह कदम उन छात्रों के लिए लाभकारी साबित होगा जो किसी कारणवश सीयूईटी परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए थे। अब मेरिट आधारित प्रवेश प्रक्रिया से उन्हें भी उच्च शिक्षा का अवसर मिल सकेगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 11 सितंबर है, ऐसे में इच्छुक छात्र जल्द से जल्द पंजीकरण कर सकते हैं।

इंडिया इंटरनेशनल ग्रैंड ट्रेड फेयर बना बेहद खास

देहरादून। इंडिया इंटरनेशनल ग्रैंड ट्रेड फेयर में दर्शकों और खरीदारों के लिए बेहद खास और यादगार साबित हुआ। हजारों लोगों ने मेले में पहुंचकर न केवल जमकर खरीदारी की बल्कि तरह-तरह के स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद भी उठाया। हर स्टॉल पर खरीददारों की भीड़ देखने को मिली।

भव्य और आकर्षक इस मेले में जहां एक ओर नेपाल की कुर्तियां, दुबई के परफ्यूम, हिमाचल की स्टैंडर्ड क्रॉकरी, मुंबई की स्पेशल भेल, और चना जोर गरम लोगों को खूब भाए, वहीं दिल्ली के रियल्टो लाइफस्टाइल का लग्जरी आउटडोर फनह्नचर और स्विंग झूला खरीदारों के बीच आकर्षण का केंद्र बना रहा। खास तौर पर मेले में अंतरराष्ट्रीय और घरेलू स्टॉलों पर खरीदारी का जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। इसके अलावा अफगानिस्तान के नेचुरल ड्राई फ्रूट्स, थाईलैंड का बैंकॉक कलेक्शन, दुबई की मिठाइयां, जयपुर की एक्सक्लूसिव चूड़ियां और मुंबई की कुर्तियां भी लोगों की पहली पसंद बनीं। हर राज्य और देश से आए स्टॉलों ने अपनी खास पहचान बनाई और खरीददारों को आकर्षित किया।

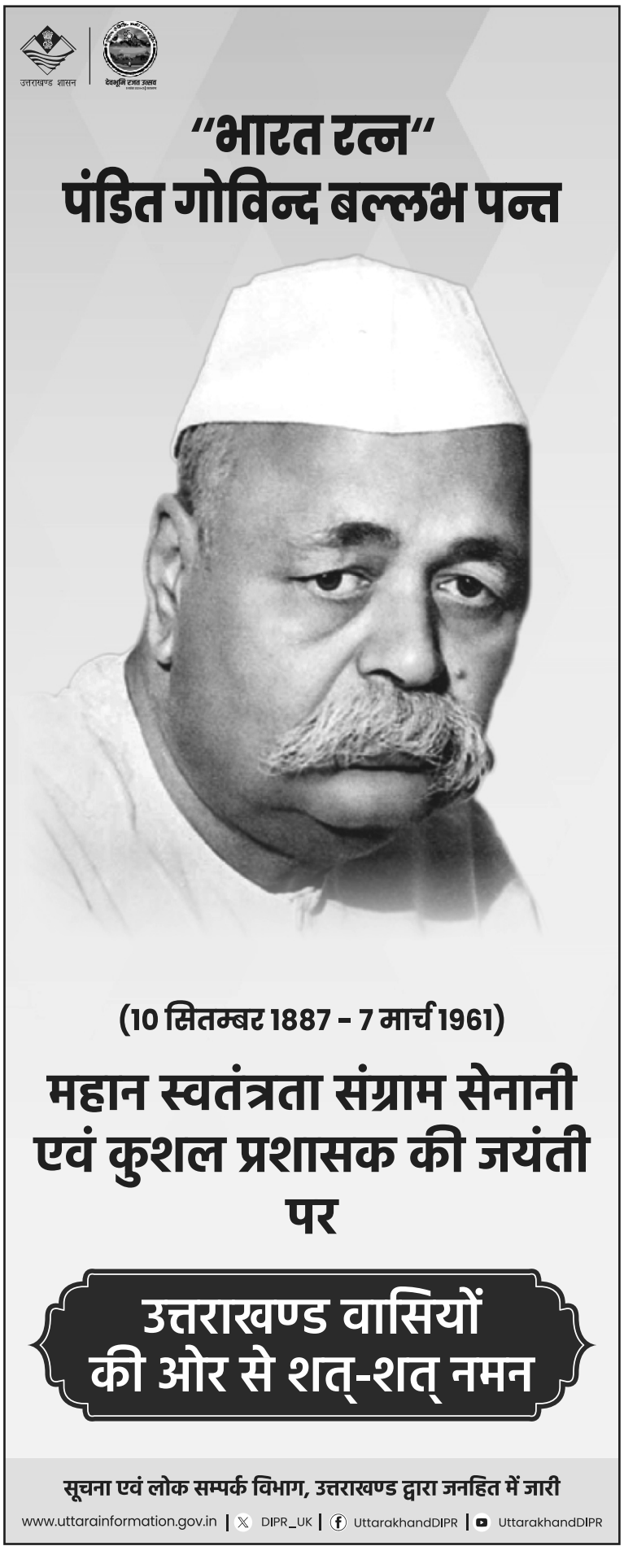

शिक्षा विभाग में 2364 चतुर्थ श्रेणी पदों पर होगी शीघ्र भर्ती

देहरादून। विद्यालयी शिक्षा विभाग के विभिन्न कार्यालयों एवं विद्यालयों में लम्बे समय से रिक्त पड़े 2364 चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों के पदों पर शीघ्र भतह्न की जायेगी। इन सभी पदों को आउटसोर्स के माध्यम से भरा जायेगा, जिसमें स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता दी जायेगी। कार्मिकों की शीघ्र तैनाती के लिये विभागीय अधिकारियों भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दे दिये गये हैं।

विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ॰ धन सिंह रावत ने मीडिया को जारी बयान में बताया कि राज्य सरकार शिक्षा विभाग में बुनियादी ढ़ांचे के साथ ही मानव संसाधन उपलब्ध कराने में जुटी है। इसी कड़ी में सरकार ने विभाग के विभिन्न कार्यालयों व विद्यालयों में सृजित चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों के 2364 रिक्त पदों (मृत संवर्ग) को आउटसोर्स के पदों में परिवर्तित करने की मंजूरी दे दी है, जिसका शासनादेश भी जारी कर दिया गया है। जिसके तहत महानिदेशालय कार्यालय, निदेशालय माध्यमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा एवं अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण सहित एससीईआरटी, बोर्ड कार्यालय रामनगर, मण्डलीय अपर निदेशक कार्यालय माध्यमिक/प्राथमिक (गढ़वाल व कुमाऊं), समस्त डायट, मुख्य शिक्षा अधिकारी व जिला शिक्षा अधिकारी मध्यमिक व बेसिक कार्यालय में कुल 334 चतुर्थ श्रेणी के पदों को आउटसोर्स में परिवर्तित कर दिया है।

इसी प्रकार 1000 छात्र संख्या से अधिक प्रत्येक इंटर कॉलेज में परिचारक के 2, स्वच्छक/सह चौकीदार के 1 पद को आउटसोर्स के पदों में परिवर्तित किया गया है। जबकि 500 से 1000 छात्र संख्या वाले इंटर कॉलेजों में 1-1 परिचारक व चौकीदार, 500 छात्र संख्या से नीचे इंटर कॉलेजों व हाईस्कूलों में 1-1 चौकीदार के पद आटसोर्स के लिये स्वीकृत किये गये हैं। जबकि ऐसे नवीन उच्चीकृत विद्यालय जिनमें चतुर्थ श्रेणी व स्वच्छक के पद सृजित नहीं है वहां भी चौकीदार का 1 पद आउटसोर्स के तहत स्वीकृत किया गया है। इस प्रकार राजकीय विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी के 2023 पदों को आउटसोर्सिंग के पदों में परिवर्तित कर दिया गया है। विभगाय मंत्री ने बताया कि चतुर्थ श्रेणी के कुल 2364 पदों को शीघ्र ही आउटसोर्स के माध्यम से भरा जायेगा, जिसमें स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता दी जायेगा। आउटसोर्स से तैनात कार्मिकों को प्रत्येक माह 15,000 रूपये मानदेय दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों की नियुक्ति में राज्य में प्रचलित आरक्षण नियमों का पूर्णत: पालन सुनिश्चित किया जायेगा, जिसके निर्देश विभागीय अधिकारियों को दे दिये गये हैं।

केदारनाथ हेली सेवा हुई महंगी

देहरादून। केदारनाथ धाम जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए हेली सेवा से यात्रा अब पहले से महंगी हो गई है। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण (यूकाडा) ने हेलिकॉप्टर सेवाओं के किराये में करीब 46 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी कर दी है। नई दरें 15 सितंबर से लागू होंगी और इसके लिए टिकट बुकिंग 10 सितंबर से आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर शुरू होगी।

इस साल 2 मई से हेली सेवा की शुरुआत हुई थी, लेकिन शुरुआती चरण में उत्तरकाशी और केदार घाटी में हुई दुर्घटनाओं के कारण सेवाएं रोकनी पड़ी थीं। अब दूसरे चरण में 15 सितंबर से सेवाएं नई एसओपी के तहत दोबारा शुरू की जा रही हैं। गृह सचिव शैलेश बगौली की अध्यक्षता में गठित 10 सदस्यीय समिति ने सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए दिशा-निर्देश तय किए हैं।

यूकाडा के सीईओ आशीष चौहान के अनुसार, गुप्तकाशी, फाटा और सिरसी से केदारनाथ के लिए चलने वाली हेली सेवाओं में सीटों और शटल उड़ानों की संख्या सीमित होने के चलते किराये में इजाफा किया गया है।

आपदा के बीच परंपरा कायम, दयारा बुग्याल में 20 दिन बाद मनाया गया अंडुड़ी मेला

उत्तरकाशी। दयारा बुग्याल में इस वर्ष पारंपरिक अंडुड़ी मेला (बटर फेस्टिवल) धराली आपदा के कारण तय तिथि से 20 दिन बाद आयोजित किया गया। रैथल और आसपास के ग्रामीणों ने परंपरा निभाते हुए दूध-दही, मक्खन की होली खेली और राधा-कृष्ण बने पात्रों ने दही की हांडी फोड़कर उत्सव का शुभारंभ किया।

आमतौर पर दयारा पर्यटन समिति और ग्रामीण हर साल भाद्रपद संक्रांति के दिन यह मेला मनाते हैं। सावन में बुग्यालों में मवेशियों के साथ रहने वाले लोग दूध-दही और मक्खन एकत्र करते हैं, जिन्हें बाद में देवताओं और वनदेवियों को भोग स्वरूप अर्पित किया जाता है। इस बार आपदा के कारण केवल गांव के लोगों ने ही सीमित रूप से यह पर्व मनाया।

आयोजित मेले में ढोल-दमाऊं की थाप पर ग्रामीणों ने रासो-तांदी किया और क्षेत्र की खुशहाली की कामना की। समिति अध्यक्ष मनोज राणा और सदस्य पृथ्वीराज राणा ने बताया कि आयोजन से पहले शुक्रवार शाम धराली आपदा में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए श्रद्धांजलि सभा रखी गई।

मेले के समापन पर रैथल में सांस्कृतिक संध्या आयोजित हुई, जिसमें स्थानीय कलाकारों ने पारंपरिक प्रस्तुतियों से माहौल को भक्तिमय और सांस्कृतिक रंगों से सराबोर कर दिया।

मुख्यमंत्री धामी ने डालनवाला थाने में 13 लॉन्ग रेंज आधुनिक सायरनों का किया लोकार्पण

लॉन्ग रेंज आधुनिक सायरनों का लोकार्पण करते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने थाना डालनवाला परिसर में स्थापित 13 लॉन्ग रेंज आधुनिक सायरनों का लोकार्पण किया। यह पहल राज्य की आपदा प्रबंधन प्रणाली को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में उत्तराखण्ड पुलिस का एक महत्वपूर्ण कदम है।

मुख्यमंत्री पुक्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड एक आपदा संभावित राज्य है, जहां भूस्खलन, बादल फटना, बाढ़ और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाएं समय-समय पर चुनौती देती रहती हैं। ऐसे में समय रहते चेतावनी और सूचना प्रसारण से जानमाल की क्षति को काफी हद तक कम किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि 8 और 16 किलोमीटर की रेंज वाले ये अत्याधुनिक सायरन न केवल प्राकृतिक आपदाओं में चेतावनी देंगे, बल्कि नागरिक सुरक्षा और जागरूकता बढ़ाने में भी अहम भूमिका निभाएंगे।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस प्रणाली का नियमित परीक्षण किया जाए और जनता को इसके बारे में जागरूक किया जाए, ताकि आपात स्थिति में इसका अधिकतम लाभ उठाया जा सके। उन्होंने पुलिस एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा किए जा रहे संयुक्त प्रयासों की सराहना की। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने डालनवाला थाने में स्थापित बाल थाने का निरीक्षण भी किया। साथ ही सेवानिवृत पुलिस कर्मियों, उत्तराखंड पीसीएस एसोसिएशन तथा उत्तराखंड पुलिस अधिकारियों एवं कार्मिकों ने मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष में सहायता राशि के चेक भेंट किए।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, सुबोध उनियाल, विधायक खजान दास, पुलिस महानिदेशक, आपदा प्रबंधन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, जिलाधिकारी देहरादून सहित अनेक जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

देहरादून का ऐतिहासिक घण्टाघर नये रूप में, सीएम धामी ने किया लोकार्पण

संवाददाता

देहरादून। उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजधानी देहरादून के ऐतिहासिक घण्टाघर के भव्य रूपांतरण और स्वचालित प्रकाश व्यवस्था का लोकार्पण किया। शहर की पहचान रहे इस धरोहर का लगभग डेढ़ करोड़ रुपये की लागत से सौंदर्यीकरण किया गया है। इसके नए स्वरूप से न केवल शहर की शोभा बढ़ेगी, बल्कि पर्यटकों के लिए भी यह स्थल आकर्षण का केंद्र बनेगा।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए निर्मित चार आधुनिक हिलांस-कम-किचन आउटलेट्स का भी शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल मातृशक्ति को स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में सशक्त बनाएगी तथा उत्तराखण्ड के पारंपरिक और जैविक उत्पादों को नया बाजार उपलब्ध कराएगी। देहरादून में कलेक्ट्रेट, कोरोनेशन अस्पताल, गुच्चुपानी और आईएसबीटी में स्थापित हिलांस कैंटीनें आम लोगों को गुणवत्तापूर्ण वस्तुएं सस्ती दरों पर उपलब्ध कराएंगी।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि घण्टाघर का नया स्वरूप देहरादूनवासियों के लिए गर्व का विषय है। स्वचालित प्रकाश व्यवस्था इसे रात्रि में भी जीवंत बनाएगी और शहर की नाइटलाइफ को नया आकर्षण प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल शहर के सौंदर्यीकरण तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक सरोकारों और जनहित से जुड़े मुद्दों को भी प्राथमिकता दी जा रही है।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने बाल भिक्षावृत्ति निवारण अभियान का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि विशेष टीमों और रेस्क्यू वाहनों की मदद से अब तक 82 बच्चों को भिक्षा की विवशता से निकालकर शिक्षा से जोड़ा गया है। साधूराम इंटर कॉलेज में इनके लिए लगभग डेढ़ करोड़ रुपये की लागत से इंटेंसिव केयर सेंटर भी बनाया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार सृजन पर निरंतर कार्य कर रही है। देहरादून में इस समय लगभग 1400 करोड़ रुपये की विकास योजनाएँ प्रगति पर हैं। शहर में 30 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जा रहा है और 11 स्थानों पर चार्जिंग स्टेशन बनाए गए हैं। ट्रैफिक और पार्किंग की समस्या को दूर करने के लिए भूमिगत पार्किंग और रिस्पना-बिंदाल नदियों पर एलिवेटेड रोड परियोजना की भी योजना तैयार की जा रही है।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, सुबोध उनियाल, विधायक खजान दास, जिलाधिकारी सविन बंसल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह, मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह, व्यापारीगण और बड़ी संख्या में स्थानीय जनता मौजूद रही।

अर्द्धकुंभ 2027 के लिए स्वास्थ्य विभाग का मास्टर प्लान तैयार, श्रद्धालुओं को मिलेगी अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाएं

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार ने 2027 में हरिद्वार में होने वाले अर्द्धकुंभ मेले की तैयारियाँ तेज कर दी हैं। इस क्रम में स्वास्थ्य विभाग ने तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक विस्तृत मास्टर प्लान तैयार किया है। विभाग ने लगभग 54 करोड़ रुपये का अनुमानित बजट प्रस्तावित किया है, जिसमें स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार के कार्य शामिल हैं।

स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने बताया कि अर्द्धकुंभ के दौरान किसी भी श्रद्धालु को चिकित्सा सुविधा की कमी महसूस न हो, इसके लिए विशेष इंतज़ाम किए जा रहे हैं। योजना के तहत 2924 बेड आरक्षित, 40 एम्बुलेंस की तैनाती, आधुनिक अस्पताल भवन और अत्याधुनिक मशीनें शामिल होंगी।

डॉ. कुमार ने बताया कि 35 अस्थायी अस्पतालों में 373 बेड, कुम्भ क्षेत्र के 13 सरकारी अस्पतालों में 1101 बेड और

निजी अस्पतालों में 1450 बेड की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा, 24 नई एम्बुलेंस खरीदी जाएंगी, जिनमें एडवांस और बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम वाली एम्बुलेंस शामिल होंगी।

श्रद्धालुओं के खानपान की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए तीन नई फूड सेफ्टी वैन खरीदी जाएंगी, जो मेला क्षेत्र में खाने-पीने की वस्तुओं की जांच करेंगी। वहीं, रोशनाबाद में ड्रग वायर हाउस का निर्माण किया जाएगा, जिसमें दवाओं के भंडारण और आपूर्ति की उन्नत व्यवस्था होगी।

संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए 25 लाख रुपये की लागत से पाँच माउंटेबल फॉगिंग मशीन और 35 पोर्टेबल फॉगिंग मशीनें खरीदी जाएंगी। इसके साथ ही भूपतवाला अस्पताल में नई डॉप्लर अल्ट्रासाउंड और एक्सरे सीआर मशीन जैसी सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएंगी।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि 2027 का अर्द्धकुंभ 'दिव्य और भव्य' होगा। यह केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक ही नहीं, बल्कि उत्तराखंड की संस्कृति और समृद्धि की झलक भी प्रस्तुत करेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि हर श्रद्धालु सुरक्षित, स्वस्थ और संतुष्ट अनुभव लेकर लौटे।

स्वास्थ्य सचिव ने स्पष्ट किया कि स्वास्थ्य विभाग कुंभ मेले के लिए समन्वित ढंग से काम कर रहा है और सभी विभागों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित कर सुविधाओं को मजबूत बनाने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए जा रहे हैं।

राज्य का पहला आधुनिक इंटेंसिव केयर सेंटर, भिक्षा से शिक्षा की ओर

देहरादून। मुख्यमंत्री की प्रेरणा एवं निर्देशन में जिला प्रशासन देहरादून द्वारा जिलाधिकारी सविन बंसल के नेतृत्व में बाल भिक्षावृत्ति, बाल मजदूरी से रेस्क्यू किए जा रहे बच्चों के मन रिफश्वर्म हेतु आधुनिक इंटेंसिव केयर सेंटर बनाया गया है, जहां से बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि देहरादून में बाल भिक्षावृत्ति निवारण के लिए भी एक विशिष्ट प्रयास किया जा रहा है, जिसके माध्यम से बालक-बालिकाओं को 'भिक्षा की विवशता से निकालकर शिक्षा के अधिकार' से जोड़ा जाएगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 3 रेस्क्यू वाहनों के साथ अंतरविभागीय टीम गठित की गई है। होमगार्ड, चाइल्ड हेल्पलाइन, शिक्षा विभाग, श्रम विभाग, पुलिस विभाग और कई गैर-सरकारी संस्थाओं को इस टीम में सम्मिलित किया गया है।

जिला प्रशासन की टीम द्वारा टीम द्वारा पहले चरण में 51 बच्चों को रेस्क्यू

कराकर विभिन्न स्कूलों में डाला जा चुका है। दूसरे चरण में 31 बच्चों को राजकीय प्राथमिक विद्यालय परेड ग्राउंड और साधूराम इंटर कश्वलेज में दाखिला दिलाया गया है।हम रेस्क्यू किए बच्चों के लिए डेढ़ करोड़ रुपए से अधिक की लागत से साधूराम इंटर कश्वलेज में इंटेसिव केयर सेंटर का निर्माण भी करा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम इस प्रयास को तब तक जारी रखेंगे, जब तक हमारे राज्य का प्रत्येक बच्चा स्कूल नहीं जाने लगता।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक सुबोध भट्ट द्वारा एल.के. प्रिंटर्स 74/9, आराघर, देहरादून (उत्तराखंड) से मुद्रित एवं मोहकमपुर कलां, माजरी मी, पो0ओ0 नवादा, देहरादून, उत्तराखंड से प्रकाशित।
सम्पादक : सुबोध भट्ट मो0 9837383994, email : subodhbhatt09@gmail.com
Web site : harshitatimes.com, facebook page : harshitatimes.com, email : harshitatimes09@gmail.com,